stated that while a blanket writing off of the agricultural and cooperative loans have very serious repercussions in respect not only of recycling of funds but also of future growth of cooperative institutions, circumstances may exist in some states which necessitate some action being taken by them. The State concerned is the best judge in this matter. The Finance Minister appealed to the State to excercise the utmost caution and see that they do not erode the confidence of the people in respect of institutions as institutions of credit.

(b) No Central grant is proposed to be provided by the Central Government to the State Governments for this purpose.

(c) Government of Tamil Nadu announced their decision to write off Rs. 16 crores of taccavi loans and Rs. 42 crores of principal and interest on cooperative loans outstanding against small farmers. The Government of Maharashtra contemplates paying the principal and interest due from small farmers as on 30-6-79 to the respective financial institutions and has made a budget provision of Rs. 49 crores for this purpose. The Government of Kerala announced the decision to waive interest on all loans taken by farmers owning less than 2 hectares prior to 1-4-76 and to make good the less sustained by the credit agencies on this score. The Government of Orissa proposed to provide debt relief to farmers in chronically drought affected areas and has sought central grant of Rs. 22.50 crores for this purpose.

पर्यटन के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय नीति

673. **श्री अशोक गहलोत :**

श्री चिरंजी लाल शर्मा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पर्यटन के संवर्धन के लिए किसी राष्ट्रीय नीति का अनुसरण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राष्ट्रीय नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग). पर्यटन के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

जीवन रक्षक औषधियों तथा बनस्पति तेल पर बिक्री-कर

674. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1980 में दिल्ली में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में जीवन रक्षक औषधियों और बनस्पति तेल पर से बिक्री कर हटाने और उसके स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के बारे में निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों ने इस का विरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या है और उन्होंने किस आधार पर इसका विरोध किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) . (क) (i) बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने (ii) केन्द्रीय बिक्री कर; (iii) राज्य बिक्री कर और (iv) चुंगी से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए 16 और 17 सितम्बर 1980 को दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था । सम्मेलन के समापन अधिवेशन में एक संकल्प स्वीकार किया गया था । संकल्प में समाहित एक मद इस आशय की थी कि हाथी समिति द्वारा सूचीबद्ध जीवन रक्षक औषधियों और